item which appeared in the Patriot on the 15th January, 1985 to the effect that research work of the Indian Council of Agriculture Research in North Eastern Region carried out at the Umroi Farm Complex near Shillong suffered a major set back due to the strike by labourers; and

(b) if so, what action Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWA NA): (a) Yes, Sir. The casual workers and a few regular technical staff members went on strike on 26-12-85 and indulged in acts of indiscipline and damaged experimental plots and a few animals.

(b) The Director of the Research Complex declared a lock-out from 6-1-86 to save the Institute property. Also, at Council's request the State Government posted police at the Farm and thus prevented further loss. Through the mediation of the Home Minister of Meghalaya State, the labourers and the staff have resumed duty from 1.2.86.

**मध्य प्रदेश में नीमच और मंदसौर में दूरदर्शन रिले केन्द्र**

542. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीमच और मन्दसौर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो यह कब किया गया और सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1985 86 के दौरान मंदसौर में कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां, तो यह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा और

(ग) क्या मंदसौर और नीमच की नगर पालिकाओं ने अपने-अपने नगरों में डिस्क एन्टीना या दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने हेतु, मंत्रालय को कोई पत्र भेजा है, यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) और (ख) मंदसौर और नीमच में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई है। तथापि इनमें से किसी भी स्थान पर उपयुक्त जगहों का चयन करने के लिये अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। 1985 86 के दौरान नई स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिये उपलब्ध सीमित धनराशि के कारण इन स्कीमों के लिये अभी तक औपचारिक स्वीकृति नहीं दी गई है । इस अवस्था पर पक्के रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि मंदसौर या नीमच में रिले ट्रांसमीटर कब तक स्थापित हो जावेंगे ।

(ग) नगरपालिका, नीमच के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उस स्कीम का ब्यौरा मांगा गया था जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, निजी संगठनों आदि को अपने अपने क्षेत्रों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु धनराशि लगाने की अनुमति दी गई है । उसे ब्यौरा विधिवत भेज दिया गया था ।

**बाल्को को बाक्साइट की सप्लाई**

543. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "बाल्को" ने उड़ीसा के गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र से बाक्साइट प्राप्त करने की कोशिश की है ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक और फल्का क्षेत्र के बाक्साइट के भंडार तेजी से समाप्त हो रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार "बाल्को" को बाक्साइट की सप्लाई नहीं कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो किन अन्य स्रोतों से "बाल्को" को बाक्साइट सप्लाई किए जाने की संभावना है ताकि कारखाने के उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बाल्को) इस समय मंधर्मदन में अपनी निजी बाक्साइट खान का विकास कर रही है ताकि मध्य प्रदेश में फुटकापहाड़ तथा अमरकंटक स्थित दोनों बाक्साइट खानों का प्रतिस्थापन किया जा सके, जिनके भंडार तेजी से घटते जा रहे हैं । अमरकंटक तथा फुटकापहाड़ में खनन के अलावा, बाल्को इस समय उत्तर प्रदेश राज्य खनन विकास निगम तथा मध्य प्रदेश राज्य खान विकास निगम से भी कुछ मात्रा में बाक्साइट की खरीद करके अपनी जरूरत पूरी कर रही है । उड़ीसा राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से बाक्साइट पूर्ति के बारे में बाल्को को अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

## नावथा में ताप्ती नदी पर बांध बनाने की संयुक्त योजना

544. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने नावथा में ताप्ती नदी पर बांध बनाने की कोई संयुक्त योजना तैयार की थी और क्या इस प्रयोजन हेतु कोई शिलान्यास किया गया था;

(ख) उक्त बांध को बनाने हेतु दोनों राज्यों में हुए करार का ब्यौरा क्या है तथा इसके निर्माण में केन्द्रीय सरकार का क्या योगदान है ; और

(ग) इस परियोजना में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों ने नावथा में ताप्ती नदी पर एक संयुक्त परियोजना का निर्माण करने और जल तथा लागत में सहभागिता की सहमति दी है । केन्द्र सरकार द्वारा लागत में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है । नावथा बांध की आधार-शिला रखे जाने के बारे में केन्द्र को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) परियोजना को योजना में शामिल करने के लिए अभी स्वीकृति नहीं दी गई है । तथापि, यह पता चला है कि यह निर्माण के प्रारम्भिक चरण में है ।

## मध्य प्रदेश में सुलभ शौचालयों का निर्माण

545. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983 से 1985 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में कितने गांवों में सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया है तथा उनकी निर्माण लागत कितनी आई है ;

(ख) इन शौचालयों में से कितने शौचालय संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि शौचालयों के निर्माण में काफी अनियमितताएं बरती गई हैं तथा इनके निर्माण का स्तर घटिया है ;

(घ) क्या इसकी जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1983 से 1985 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग